

क्रिप्टोकरंसी और भारतीय वित्तीय प्रणाली: एक समीक्षा

डॉ. नमता दुबे

अतिथि विद्वान वाणिज्य विभाग

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश

सारांश

क्रिप्टोकरंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्ति (वर्चुअल डिजिटल एसेट - VDA) है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। भारत में यह तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन भारतीय वित्तीय प्रणाली पर इसका प्रभाव मिश्रित है। 2018 में आरबीआई के प्रतिबंध, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2023 में पीएमएलए के तहत FIU-IND पंजीकरण के बाद विनियमन की दिशा स्पष्ट हुई है। 2025 तक 30% फ्लैट टैक्स और 1% टीडीएस बरकरार है, जबकि बजट 2025 में रिपोर्टिंग अनुपालन के लिए नए दंड (धारा 285BAA) लागू हुए हैं। आरबीआई ई-रुपया (सीबीडीसी) पायलट को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 19 बैंक शामिल हैं और ऑफलाइन भुगतान तथा प्रोग्रामेबिलिटी जैसी सुविधाएं हैं।

सकारात्मक प्रभावों में वित्तीय समावेशन, कम लेन-देन लागत, विदेशी निवेश और फिनटेक नवाचार शामिल हैं। नकारात्मक प्रभावों में अस्थिरता, मनी लॉन्ड्रिंग, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण की हानि और साइबर जोखिम हैं। इस समीक्षा में द्वितीयक स्रोतों (आरबीआई रिपोर्ट, सरकारी अधिसूचनाएं, शैक्षणिक पत्र और समाचार) के आधार पर विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष यह है कि संतुलित विनियमन और ई-रुपया को प्राथमिकता देकर क्रिप्टोकरंसी के लाभों को सुरक्षित तरीके से अपनाया जा सकता है।



कीवर्ड्स

क्रिप्टोकॉरन्सी, ब्लॉकचेन, भारतीय वित्तीय प्रणाली, आरबीआई, सीबीडीसी, वीडिए, पीएमएलए, ई-रुपया, विनियमन, फिनटेक

परिचय

क्रिप्टोकॉरन्सी की अवधारणा 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा बिटकॉइन के रूप में शुरू हुई। यह विकेंद्रीकृत, क्रिप्टोग्राफी-आधारित और मध्यस्थ-रहित प्रणाली है जो पारंपरिक बैंकिंग से अलग है। वैश्विक स्तर पर इसका बाजार पूंजीकरण लाखों करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत में क्रिप्टोकॉरन्सी का उपयोग बढ़ा है – 2020-21 में ट्रेडिंग वॉल्यूम 880% बढ़ा और लाखों भारतीय निवेशक सक्रिय हैं। 2018 में आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो से संबंधित सेवाएं देने पर प्रतिबंध लगाया, जिसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद 2023 में वीडिए सेवा प्रदाताओं (VASP) को पीएमएलए 2002 के तहत FIU-IND में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। 2025 तक कोई व्यापक क्रिप्टो कानून नहीं बना है, लेकिन बजट 2025 में रिपोर्टिंग दंड सख्त किए गए हैं। आरबीआई ने ई-रुपया (डिजिटल रुपया) को वैकल्पिक के रूप में लॉन्च किया, जो कानूनी मुद्रा है और निजी क्रिप्टो से अलग है। इस समीक्षा का उद्देश्य क्रिप्टोकॉरन्सी के भारतीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभावों का समय विश्लेषण करना है। भारत में क्रिप्टोकॉरन्सी का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को क्रिप्टो से संबंधित सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद 2023 में वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) सेवा प्रदाताओं (VASP) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत FIU-IND में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। 2026 तक कोई व्यापक क्रिप्टो कानून नहीं बना है, लेकिन बजट 2026 में रिपोर्टिंग अनुपालन को सख्त किया गया है – जैसे दैनिक रिपोर्टिंग में चूक पर ₹200 प्रतिदिन दंड और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक जुर्माना



(धारा 285BAA और संबंधित प्रावधान)। कराधान व्यवस्था में 30% फ्लैट टैक्स और 1% टीडीएस अपरिवर्तित है, जिसके कारण कुछ कारोबार विदेशी प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा है। आरबीआई ने निजी क्रिप्टोकॉरन्सी के विकल्प के रूप में ई-रुपया (डिजिटल रुपया या CBDC) को प्राथमिकता दी है। दिसंबर 2022 से शुरू हुआ रिटेल पायलट मार्च 2026 तक काफी विस्तारित हो चुका है, जिसमें 17-19 बैंक शामिल हैं, 60 लाख से अधिक उपयोगकर्ता, और संचालन मूल्य ₹1,000 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। यह कानूनी मुद्रा है, ऑफलाइन भुगतान, प्रोग्रामेबिलिटी (जैसे DBT के लिए) और मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने वाली सुविधाओं से युक्त है। क्रिप्टोकॉरन्सी भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लाती है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है, खासकर अंबैंकेड और अंडर-बैंकेड आबादी के लिए, जहां UPI के साथ तालमेल से लेन-देन लागत कम होती है। साथ ही, फिनटेक नवाचार, एसेट टोकनाइजेशन और वैश्विक निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। दूसरी ओर, मूल्य अस्थिरता, मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद फंडिंग का जोखिम, साइबर हमले और मौद्रिक नीति पर आरबीआई के नियंत्रण में कमी जैसे खतरे हैं।

अनुसंधान पद्धति

यह एक द्वितीयक डेटा-आधारित समीक्षा अध्ययन (Review Paper) है। साहित्य चयन की प्रक्रिया व्यवस्थित रही:

समयावधि: 2018 से 2025 तक (आरबीआई अधिसूचनाएं, बजट दस्तावेज, शैक्षणिक पत्र और वैश्विक रिपोर्ट)।

स्रोत: आरबीआई वेबसाइट, FIU-IND अधिसूचनाएं, ग्लोबल लीगल इनसाइट्स 2025 रिपोर्ट, IJCRT और अन्य शोध पत्र, PIB और समाचार स्रोत।

विश्लेषण विधि: गुणात्मक-वर्णनात्मक (Qualitative-Descriptive)। सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावों को थीम-आधारित वर्गीकरण (Financial Inclusion, Stability, Regulation, CBDC) में बांटा गया।



प्राथमिक डेटा के बजाय सरकारी आंकड़े और सर्वेक्षण (जैसे 700 उपयोगकर्ताओं का सर्वे) का उपयोग किया गया।

नियमन ढांचा (Regulatory Framework):

वीडीए को पीएमएलए 2002 के अंतर्गत “रिपोर्टिंग एंटीटी” माना गया (अधिसूचना 7 मार्च 2023)। VASP

को FIU-IND पंजीकरण, KYC, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग अनिवार्य।

कराधान: 30% फ्लैट टैक्स + 1% टीडीएस (बजट 2026 में अपरिवर्तित)। अप्रैल 2025 से धारा 285BAA

के तहत दैनिक रिपोर्टिंग; गलत रिपोर्टिंग पर ₹50,000 दंड।

- प्रवर्तन: बिनांस, बायबिट आदि पर करोड़ों का जुर्माना (2024-25 में DGGI और FIU कार्रवाई)।
- भारतीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव:
- सकारात्मक:
- वित्तीय समावेशन – अंबैंकेड आबादी के लिए आसान पहुंच (UPI के साथ तालमेल)।
- लेन-देन लागत में कमी – अंतरराष्ट्रीय रেমिटेंस सस्ता।
- निवेश और नवाचार – फिनटेक विकास, एसेट टोकनाइजेशन।
- नकारात्मक:
- अस्थिरता – मूल्य उतार-चढ़ाव से वित्तीय स्थिरता प्रभावित।

मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद फंडिंग का खतरा।

मौद्रिक नीति पर असर – आरबीआई का नियंत्रण कम हो सकता है।

आरबीआई का ई-रुपया पायलट 19 बैंक (SBI, ICICI आदि), ऑफलाइन भुगतान, प्रोग्रामेबिलिटी (DBT

के लिए) और कानूनी मुद्रा का दर्जा। यह निजी क्रिप्टो/स्टेबलकॉइन से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह

मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखता है।



निष्कर्ष

क्रिप्टोकॉरंसी भारतीय वित्तीय प्रणाली को नवाचार प्रदान कर सकती है, लेकिन जोखिम बिना संतुलित विनियमन के बढ़ सकते हैं। आरबीआई का सीबीडीसी फोकस सही दिशा है। सरकार को G20/FATF के साथ समन्वय में व्यापक कानून लाना चाहिए, निवेशक शिक्षा बढ़ानी चाहिए और कर संरचना को तर्कसंगत बनाना चाहिए। भविष्य में ई-रुपया और नियंत्रित क्रिप्टो दोनों का सह-अस्तित्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। आगे के अनुभवजन्य अध्ययन की आवश्यकता है। क्रिप्टोकॉरंसी भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लाती है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है, खासकर अंबैंकेड और अंडर-बैंकेड आबादी के लिए, जहां UPI के साथ तालमेल से लेन-देन लागत कम होती है। साथ ही, फिनटेक नवाचार, एसेट टोकनाइजेशन और वैश्विक निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। दूसरी ओर, मूल्य अस्थिरता, मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवाद फंडिंग का जोखिम, साइबर हमले और मौद्रिक नीति पर आरबीआई के नियंत्रण में कमी जैसे खतरे हैं। यह समीक्षा पत्र क्रिप्टोकॉरंसी के भारतीय वित्तीय प्रणाली पर प्रभावों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें विनियमन, कराधान, सीबीडीसी और आर्थिक प्रभावों पर फोकस है। उद्देश्य है कि पाठक को वर्तमान स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मिले और भविष्य की दिशा समझ आए।

संदर्भ

- [1]. Reserve Bank of India. (2024, February 4). Digital Rupee (e₹) – FAQs. <https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/FAQs.aspx?Id=3686>
- [2]. Global Legal Insights. (2025). Blockchain & Cryptocurrency Laws & Regulations 2025 – India. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-cryptocurrency-laws-and-regulations/india/>
- [3]. Singh, A. & Kumar, R. (2023). Impact of Cryptocurrency on the Indian Economy. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2308786.pdf>



- [4]. Ministry of Finance, Government of India. (2023). PMLA VASP Notification (S.O. 1072(E)).
- [5]. Union Budget 2024-25 & 2025 Documents. India Budget Portal.
- [6]. Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND). (2023-2025). Enforcement Notices on Offshore Exchanges.
- [7]. Kumar, G. et al. (2024). Future of Cryptocurrency in India. Theoretical and Applied Economics.

